उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 5 | अंक 13 | 1-15 जुलाई 2022 | ₹ 20/-

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर गंभीर आरोप

- असम में पांच मुस्लिम जातियों को स्वदेशी का दर्जा
- शरिया लागू करने के लिए तालिबान कटिबद्ध
- हिजबुल्लाह के खिलाफ 30 देशों का मोर्चा
- अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में भारतीय दूसरे स्थान पर

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर गंभीर आरोप 04
असम में पांच मुस्लिम जातियों को स्वदेशी का दर्जा 07
पसमांदा मुसलमानों में भाजपा का स्नेह अभियान 09
जनसंख्या नियंत्रण पर मचा विवाद 11
पाठ्यपुस्तकों में संशोधन से उभरा नया विवाद 13

विश्व

शरिया लागू करने के लिए तालिबान कटिबद्ध 16
डेनमार्क में जिहादी हमला 17
रूसी खतरे का सामना करने के लिए नाटो की नई कमान 18
शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयास 19
अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग से दर्जनों की हत्या 20

पश्चिम एशिया

हिजबुल्लाह के खिलाफ 30 देशों का मोचा 22
सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेद उभरे 24
ईद के अवसर पर 1500 कैदी रिहा 25
तुर्की में वॉयस ऑफ अमेरिका के प्रसारण पर प्रतिबंध 26
ईरान के खिलाफ प्रतिबंध गैरकानूनी 26

अन्य

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में भारतीय दूसरे स्थान पर 27
मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार 27
मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करने की मांग 27
संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी 28
गाय की कुर्बानी न करने का निर्देश 28

सारांश

पूर्व उपराष्ट्रपति और कांग्रेसी नेता हामिद अंसारी फिर से एक गंभीर विवाद में उलझ गए हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया है कि अंसारी ने उन्हें भारत बुलाया था और भारत यात्रा में उन्हें अनेक गुप्त और संवेदनशील जानकारियां मिली थी। इस जानकारी को इस पत्रकार ने पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (आईएसआई) तक पहुंचाया। पाकिस्तानी पत्रकार के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अंसारी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा है। अंसारी ने हालांकि इस पाकिस्तानी पत्रकार से मिलने का खंडन किया है, मगर इसके बावजूद यह पाकिस्तानी पत्रकार अंसारी पर लगाए गए आरोपों पर अडिग है। अंसारी का संबंध एक कांग्रेसी परिवार से रहा है। वे भारतीय विदेश सेवा से भी संबंधित रहे हैं और अनेक देशों में भारतीय राजदूत के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। इससे पूर्व भी वे अनेक बार विवादों के घेरे में रहे हैं, मगर इस बार वे जिस विवाद में उलझे हैं वह बहुत गंभीर है। सरकार को चाहिए कि वह इस आरोप को उच्चस्तरीय जांच करवाए।

असम सरकार ने पांच मुस्लिम जातियों को मूल असमिया घोषित किया है। असम के मूल मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। असमिया मुसलमानों का आरोप है कि इन विदेशी घुसपैठियों ने उन्हें वन संपदा और रोजगार से वंचित कर दिया है। असमिया मुसलमानों की मांग पर राज्य सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने कहा है कि असम की मुस्लिम जनसंख्या हालांकि 1 करोड़ 26 लाख है, मगर उसमें से असम के मूल निवासी मात्र 40 लाख हैं। शेष सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यह तथ्य सर्वविदित है कि मोहम्मद अली जिन्ना का इरादा असम को हड़पने का था। वे इसे मुगलिस्तान का दर्जा देना चाहते थे। इसलिए मुस्लिम लीग के समर्थकों ने 1935 से एक सुनियोजित साजिश के तहत बांग्लादेशी मुसलमानों को असम में आबाद किया। इस संदर्भ में सर अकबर हैदरी और अनेक प्रमुख कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं की भूमिका भी काफी संदिग्ध रही है। यह निर्विवाद तथ्य है कि असम के नौ सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम जनसंख्या 40 से 45 प्रतिशत है। इन घुसपैठियों को भारत से निष्कासित करने के लिए अनेक बार आंदोलन चलाए गए, मगर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे पसमांदा मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने का प्रयास करें। गौरतलब है कि देश के 20-21 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या में से 16-17 करोड़ पसमांदा वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए इनके वोट पाने के लिए भाजपा ने यह नया प्रयास शुरू किया है।

अमेरिका और तीस अन्य देशों ने शिया मुसलमानों के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए एक योजना बनाने का फैसला किया है। हिजबुल्लाह को ईरान सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसका घोषित लक्ष्य इजरायल का खात्मा करना है। इसके अतिरिक्त यह अमेरिका और यूरोपीय देशों के बढ़ते हुए प्रभाव पर भी नकेल डालना चाहता है।

तालिबान अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने यह घोषणा की है कि वे हर कीमत पर अफगानिस्तान में निजाम-ए-मुस्तफा (इस्लामी शरीयत पर आधारित शासनतंत्र) को लागू करके ही दम लेंगे। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा है कि किसी भी विदेशी ताकत को हमें शरीयत को लागू करने से रोकने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि तालिबान जब से अफगानिस्तान में सत्ता में आए हैं शासनतंत्र को शरीयत निजाम में ढालने का प्रयास कर रहे हैं।

राष्ट्रीय

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर गंभीर आरोप

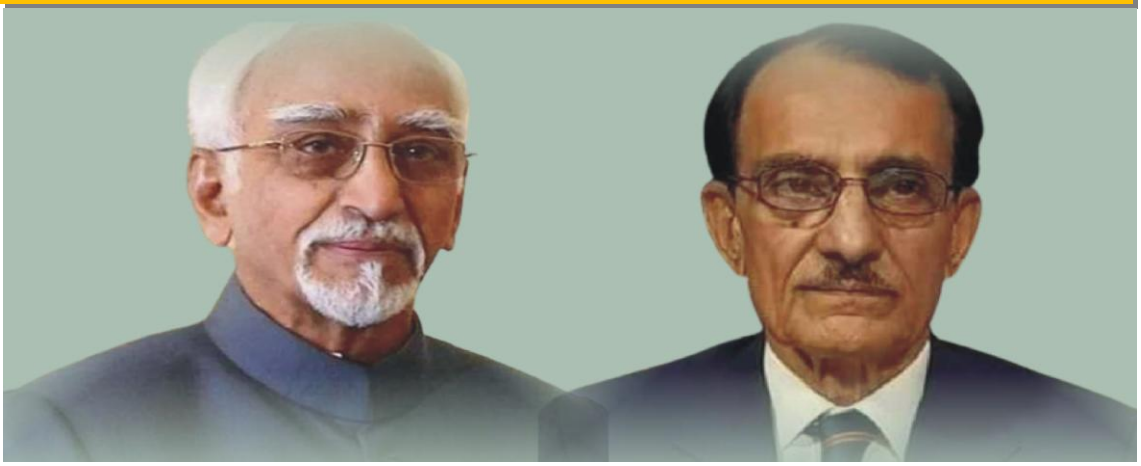

पूर्व उपराष्ट्रपति और कांग्रेसी नेता हामिद अंसारी एक नए विवाद में उलझ गए हैं। भाजपा का आरोप है कि अंसारी ने पाकिस्तान के एक पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील सूचनाएं साझा की थी, जिसे उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बता दी थी।

सालार (14 जुलाई) के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हामिद अंसारी को अपना निशाना बनाया है। अंसारी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी पत्रकार का आरोप बेबुनियाद है और वे उनसे कभी नहीं मिले हैं। इसलिए उन्हें किसी तरह की सूचना देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पाकिस्तान के विख्यात पत्रकार नुसरत मिर्जा ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि वे कई बार अंसारी के आमंत्रण पर भारत गए थे और उनसे उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई थी, वह उन्होंने पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के साथ साझा की थी। एक भारतीय पत्रकार अंकित झा की रिपोर्ट के अनुसार नुसरत मिर्जा ने 2005 से लेकर 2011 तक भारत का कई बार दौरा किया था। जबकि मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में 2010 के अपने भारतीय दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वे आतंकवाद के संबंध में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए भारत गए थे और उन्हें भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। मिर्जा ने यह भी कहा कि अंतिम बार वे 2011 में भारत गए थे और वे वहां पर मिल्ली गजट के पकाशक जफरूल इस्लाम खान से भी मिले थे। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उन्हें भारत का दौरा करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की थी। आम तौर पर किसी भी पाकिस्तानी को भारत के तीन नगरों का दौरा करने की अनुमति दी जाती है, मगर उन्हें पांच शहरों का दौरा करने की अनुमति दी गई और उन्हें वहां से कुछ विशेष संवेदनशील जानकारी जुटाने का भी संकेत दिया गया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, 'नुसरत मिर्जा ने कहा है कि भारत के दौरे के दौरान उनकी हामिद अंसारी से मुलाकात हुई

थी। इस मुलाकात में अंसारी ने उनके साथ कुछ बेहद संवेदनशील और गुप्त जानकारी साझा की थी और ऐसा एक बार नहीं बल्कि पांच बार हुआ। उन्होंने हामिद अंसारी से जो जानकारी ली थी उसे उन्होंने गुप्तचर एजेंसी को बताया और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।' कांग्रेस को निशाना बनाते हुए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार एक पत्रकार को पांच बार भारत आने का निमंत्रण देती है और उसे महत्त्वपूर्ण ख़ुफिया जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। भाटिया ने कहा कि देश की जनता पूछना चाहती है कि कांग्रेस सरकार की आतंकवाद को समाप्त करने के बारे में क्या नीति थी? कांग्रेस ने देश की संवेदनशील और गुप्त जानकारी पाकिस्तान को क्यों उपलब्ध कराई, जिसे उसने आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया? भाजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांगेस की नीति शुरू से ही देश को कमजोर करने की रही है। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे को बेबुनियाद और झूठ का पुलिंदा बताया है।

अवधनामा (14 जुलाई) के अनुसार कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक बयान जारी करके कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भाजपा के प्रवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है और उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है।

सालार (14 जुलाई) के अनुसार भाजपा द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद हामिद अंसारी ने एक वक्तव्य जारी किया है और आरोप लगाया है कि मेरे खिलाफ भाजपा जानबूझकर झूठे आरोप लगा रही है। जहां तक मिर्जा को भारत आने का आमंत्रण देने का संबंध है, विदेशी मेहमानों को विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद संबंधित संगठन सेमिनार में भाग लेने का आमंत्रण देता है। इसलिए न तो मैंने मिर्जा को आमंत्रण दिया है और न ही उनसे कभी मिला हूं। उन्होंने कहा कि जब वे ईरान में भारतीय राजदूत थे तो उन्होंने जो कुछ किया था वह केंद्र सरकार के निर्देश पर किया था। क्योंकि यह मामला बेहद संवेदनशील है इसलिए राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को देखते हुए मैं उस पर किसी तरह का प्रकाश नहीं डाल सकता। इससे पूर्व भी भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद ने अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने 28 जून 2019 को एक ट्विट में कहा था, 'जब मैं तेहरान (ईरान) में नियुक्त था तो अंसारी ईरान में भारतीय राजदूत थे। उन्होंने ईरान सरकार को ईरान में सक्रिय भारतीय गुप्तचरों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके कारण इन सभी रॉ के कर्मचारियां के जीवन को खतरा पैदा हो गया था और उनकी इस हरकत से ईरान में भारतीय गुप्तचरों का तंत्र पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया था।'

रोजनामा सहारा (14 जुलाई) के अनुसार हामिद अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि मुझ पर भाजपा झूठे आरोप लगा रही है। मैंने

उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को कभी फोन नहीं किया था। देश से गद्दारी करने का मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वह सरासर बेबुनियाद है। मैं न तो मिर्जा से कभी मिला हूं और न ही मैंने उन्हें कभी बुलाया है।

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार हामिद अंसारी ने यह भी कहा है कि यह आरोप सरासर गलत है कि मैंने नुसरत मिर्जा को कोई खुफिया और संवेदनशील जानकारी दी थी।

टिप्पणी: हामिद अंसारी का विवादों से पुराना नाता है और वे इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वे एक कट्टरपंथी मुसलमान हैं। उनका जन्म 1937 में कोलकाता में हुआ था और उनकी शिक्षा-दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। 1961 में वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और एक दर्जन से अधिक देशों में भारतीय राजदूत रहे। 1984 में उन्हें पद्म सम्मान दिया गया। 2007 में उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने उतारा और वे जीत गए। 2012 में भी उनके कार्यकाल में पांच वर्ष की वृद्धि की गई। उपराष्ट्रपति पद के विदाई समारोह में अंसारी ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं।

भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ के कुछ प्रमुख पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि जब अंसारी ईरान में राजदूत थे तो उन्होंने रॉ के एक गुप्त ऑपरेशन के बारे में जानकारी ईरान सरकार को दी थी। जिस पर ईरान सरकार ने वहां पर सक्रिय रॉ के अनेक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें संदीप कपूर का नाम प्रमुख है। जब विदेश मंत्रालय ने हामिद अंसारी से संदीप कपूर के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने भारत सरकार को यह झूठी रिपोर्ट दी कि कपूर लापता हैं। जबकि वे इस बात को भलीभांति जानते थे कि कपूर ईरान सरकार की हिरासत में हैं। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि रॉ को यह सूचना मिली थी कि कुछ कश्मीरी आतंकवादियों को ईरान के एक नगर कोम में अस्त्र-शस्त्र चलाने का गुप्त प्रशिक्षण ईरानी अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। अंसारी ने यह महत्त्वपूर्ण सूचना ईरान सरकार को लीक कर दी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था, मगर 2015 में भारत सरकार ने जब पहला योग दिवस मनाया तो उस कार्यक्रम से उपराष्ट्रपति गायब थे। उसी वर्ष गणतंत्र दिवस परेड़ में राष्ट्रीय ध्वज को अंसारी द्वारा सलामी न दिए जाने का मामला भी मीडिया में उछला था। ग्रेटर नोएडा में जब एक व्यक्ति अखलाक की हत्या कर दी गई तो अंसारी ने एक वक्तव्य में आरोप लगाया कि भारत मं मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं।

कुछ वर्ष पूर्व जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पूर्व राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया था तो अंसारी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। 2018 में जब अलीगढ विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने का विवाद उत्पन्न हुआ तो अंसारी ने उसका खुलेआम समर्थन किया था। 2018 में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरिया अदालतें स्थापित करने का भी उन्होंने समर्थन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए अंसारी ने शिकायत की थी कि देश के मुसलमानों को मोदी सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है और उन्हें विकास की योजनाओं से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है।

असम में पांच मुस्लिम जातियों को स्वदेशी का दर्जा

सियासत (7 जुलाई) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शमा ने राज्य में अवैध रूप से घुसने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों का सुराग लगाने के लिए नया हथकंडा अपनाया है। उन्होंने असम के मूल भारतीय मुसलमानों की पहचान का

काम शुरू कर दिया है और पहली किश्त के रूप में पांच मुस्लिम समुदायों की पहचान की गई है। इनमें गोरिया, मोरिया, जुलाहा, सैयद और देशो शामिल हैं। असम सरकार इन वर्गों को जनजाति का दर्जा देगी और इनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था करेगी। समाचारपत्र ने यह संदेह व्यक्त किया है कि इसके बाद वहां पर बसे हुए बांग्ला भाषियों को राज्य से निष्कासित करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा।

असम मंत्रिमंडल की बैठक में असम की पांच मुस्लिम जातियों को खिलोंजिया का दर्जा दिया गया है। देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कुछ मुस्लिम जातियों को अन्य मुसलमानों से अलग चिन्हित किया गया हो। असम सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि राज्य सरकार ने जो विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी उसकी सिफारिशों के कारण यह फैसला किया गया है, ताकि सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि खिलांजिया मुसलमान सिर्फ भारत में पैदा होने से ही नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए यह जरूरी है कि वह असमिया मुसलमान हो। असम में मुसलमानों के दो फिरके हैं एक खिलोंजिया मुसलमान और दूसरा मियां मुसलमान। मियां मुसलमान उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके असम में दाखिल हुए थे या जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। असम के लोगों का मानना है कि बांग्लादेश से आने वाले इन लोगों ने उनके वनों, नदियों और भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और वे उन्हें राजनीति, व्यापार और नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। सरकार के अनुसार असम की कुल जनसंख्या में 25-30 प्रतिशत घुसपैठिए हैं। राज्य में एक चौथाई ऐसी सीटें हैं जिन पर बांग्ला भाषी किसी भी व्यक्ति को विजयी बना सकते हैं। जबकि इन बांग्ला भाषी लोगों का कहना है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं बल्कि भारत में पैदा होने वाले बांग्ला भाषी हैं।

रोजनामा सहारा (9 जुलाई) के अनुसार असम के विपक्षी दलों द्वारा इस सरकारी निर्णय का विरोध किया गया है और कहा गया है कि सरकार मुस्लिम समाज में जानबूझकर विभाजन पैदा करना चाहती है। उनका कहना है कि असम में रहने वाले सभी मुसलमान असमिया हैं। सरकार का दावा है कि असम के मूल निवासी काफी अरसे से यह मांग कर रहे हैं कि इन घुसपैठियों को राज्य से निष्कासित किया जाए। एआईयूडीएफ के नेता अमीनुल इस्लाम ने आरोप लगाया है कि यह निर्णय मुस्लिम समाज को विभाजित करने की एक नई चाल है। भारतीय संविधान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक घोषित किया जा चुका है, मगर अब भाजपा मुस्लिम समाज को विभाजित करके उन्हें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रही है। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मोमिनुल अवल ने इस सरकारी फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मूल असमिया मुसलमानों का शोषण समाप्त हो जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा।

पृष्ठभूमिः पिछले वर्ष राज्य सरकार ने असम के पत्रकार वासबीर हुसैन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था और उसे इस बात का जिम्मा सौंपा था कि वह इस बात की सिफारिश करे कि मूल असमिया मुसलमान कौन हैं? और

बाहर से आने वाले मुसलमानों का कौन-कौन सा समूह है? इस कमेटो ने अपनी रिपोर्ट में असमिया मुसलमानों के पांच समूहों को मूल असमिया करार दिया है। असम में मुसलमानों की जनसंख्या एक करोड़ 26 लाख है, जिनमें से 40 लाख मूल असमिया हैं।

मूल असमिया मुसलमानों में देशी उल्लेखनीय हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने 1205 में बख्तियार खिलजी के हमले के समय मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। इनका संबंध अली मच राजपरिवार से बताया जाता है जो राजवंशी कोच परिवार था, जिन्होंने बख्तियार खिलजी के शासनकाल में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था।

दूसरा समूह सैयद लोगों का है। ये वे असमिया हैं जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में सूफियों के प्रभाव के कारण मुसलमान बने थे। असम के इतिहास के अनुसार 1497 में मदन पीर नामक एक सूफी मुसलमान ने धर्मांतरण किया था। कहा जाता है कि सैयद बदीउद्दीन शाह मादा उर्फ मदन पीर इराक से आए थे। जबकि 1630 में एक अन्य सूफी सैयद मोईनुद्दीन बगदादी ने भी व्यापक रूप से असमियों को मुसलमान बनाया था। इनके शिष्य सैयद कहलाते हैं।

जहां तक गोरिया मुसलमानों का संबंध है, 1615 और 1682 के बीच मुगलों के हमलों के दौरान असम के अहोम राजाओं ने काफी मुगल सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था, जिन्होंने बाद में स्थानीय महिलाओं स विवाह कर लिए। उनके वंशज गोरिया कहलाते हैं।

जहां तक मोरिया का संबंध है, 16वीं और 17वीं शताब्दो में मुस्लिम आक्रांताओं ने असम पर कई बार हमले किए थे। उनके काफी सिपाही असम में बस गए और उनके वंशज मोरिया कहलाते हैं।

जहां तक जुलाहों का संबंध है, ये लोग मूल रूप से बिहार, उड़ीसा और बंगाल के रहने वाले हैं। ये मूलत: आदिवासी हैं। ये अहोम वंश क शासनकाल में आकर असम में बसे थे। जबकि ब्रिटिश शासनकाल में भी काफी आदिवासी देश के अन्य भागों से चाय बागानों में काम करने के लिए लाए गए। इनमें स काफी लोग मुसलमान बन गए थे।

राज्य सरकार की इस घोषणा का कछारी मुसलमानों ने विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि वे बराक घाटी में सदियों से रह रहे हैं। इस क्षेत्र में 13वीं से 19वीं शताब्दी तक कछारी राजाओं का शासन था और उनके समय में काफी आदिवासियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। बराक घाटी म्ल मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष अतीकुर रहमान का कहना है कि वे मूलत: असमिया हैं और कम-से-कम 600 वर्ष से इस क्षेत्र में मुसलमान के रूप में रह रहे हैं, मगर असम की वर्तमान सरकार ने उन्हें देशी मुसलमान के रूप में मान्यता नहीं दी है। यह उनके साथ घोर अन्याय है।

वासबीर हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि मूल असमिया मुसलमानों के विकास की गति को तेज करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आदिवासियों की भांति आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं। ऑल असम गोरिया-मोरिया-देशी परिषद ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि बंगाली मुसलमानों के कारण असम के मूल मुसलमान अपनी अलग पहचान खोते जा रहे थे। एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार एक योजना के तहत बंगाली मुसलमानों को समाज से अलग कर रही है। अरिजोना विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर यास्मीन सैकिया ने कहा है कि राजनीतिक कारणों से भाजपा मुस्लिम समाज को विभाजित कर रही है, ताकि एक वर्ग को प्रलोभन देकर वह उनके मत प्राप्त कर सके। अगर राज्य सरकार मुसलमानों का कल्याण चाहती है तो वह मुस्लिम समाज को क्यों विभाजित कर रही है?

पसमांदा मुसलमानों में भाजपा का स्नेह अभियान

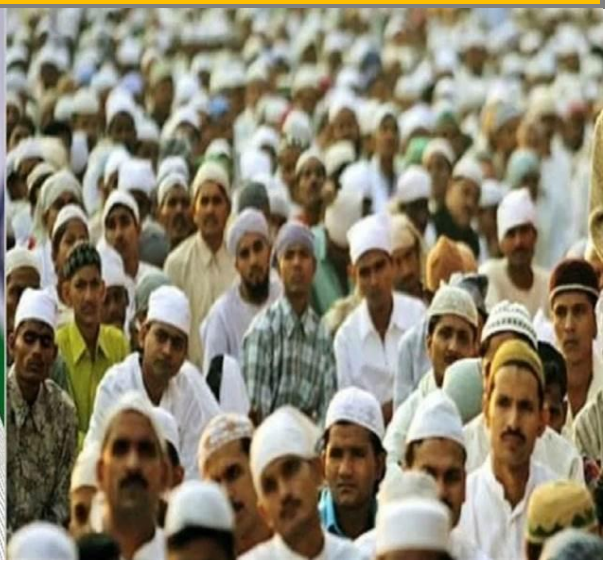

इंकलाब (4 जुलाई) के अनुसार हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे पसमांदा मुसलमानों के बीच काम करके उन्हें पार्टी से जाड़ें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के हाल के चुनाव परिणामों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव में आजमगढ़ जैसी महत्त्वपूर्ण सीट को जीत लिया है, जिसे मुस्लिम-यादव गठबंधन का गढ़ माना जाता था। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेताओं को पसमांदा मुसलमानों में काम करने की जरूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार में पसमांदा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और दानिश अंसारी को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है। अब इस बात की जरूरत है कि इस समाज को ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ा जाए।

इंकलाब (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमें पसमांदा मुसलमानों की ओर देखना चाहिए, उन्हें अपने नजदीक लाना चाहिए। अब हमें पिछड़े हुए समाज में काम करना होगा और अल्पसंख्यकों के उन वर्गों की तरफ ध्यान देना होगा जो हाशिए पर हैं। उन्हें गत आठ वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ उठाएं।

समाचारपत्र ने कहा है कि जो पत्रकार हैदराबाद में मौजूद होंगे उन्हें प्रधानमंत्री के परामर्श से हैरानी हुई होगी। उनके दिमाग में यह सवाल जरूर उभरा होगा कि क्या भाजपा की नीति बदल गई है? अब तक तो मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने और वोट का करंट शाहीन बाग तक पहुंचाने की बात हो रही थी। अब पसमांदा मुसलमानों के तुष्टीकरण की क्यों जरूरत महसूस की जा रही है? निश्चित रूप से यह बड़ा परिवर्तन है, मगर यह अचानक नहीं हुआ है। हमारा ख्याल यह है कि यह नीति उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही तय की जा चुकी थी, मगर उसे जाहिर नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री और पार्टी के अन्य नेता बार-बार लाभार्थियों का उल्लेख कर रहे थे। तब लाभार्थियों का अर्थ सिर्फ

गैरमुसलमान नहीं था, बल्कि उनमें वह मुसलमान भी शामिल थे जो गरोब हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भाजपा की नजर उनक वोटों पर भी थी। इसलिए इन लाभार्थी मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए थे।

समाचारपत्र ने कहा है कि हमारे पास इस बात के आंकड़े नहीं हैं, जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि कितने प्रतिशत गरीब मुसलमानों ने भाजपा को अपने मत दिए थे, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश में विरोधी लहर होने के बावजूद भाजपा को भारी सफलता मिली, जिसमें लाभार्थियों का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने सिर्फ यह देखा कि उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। 2014 में विकास को मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था। हालांकि यह कोशिश सफल हुई मगर इस मुद्दे पर पार्टी को वोट नहीं मिले थे। इसलिए 2019 में दलितों और पिछड़े वर्गों को भी भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह प्रयास सफल रहा, मगर बदलते हुए हालात में यह जरूरी है कि जो अन्य वर्गों के लाभार्थी हैं उनके भी वोट बटोरे जाएं। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के विवाद के कारण मुसलमानों में व्याप्त रोष के निराकरण के लिए अब भाजपा ने एक नया हथकंडा अपनाया है।

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने पसमांदा मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा उछाला है।

रोजनामा सहारा (9 जुलाई) में शाहिद ज़बेरी ने एक लेख में कहा है कि मुसलमानों के बारे में भाजपा की नीति किसी से छिपी हुई नहीं है। फिर क्या हुआ कि अचानक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद में इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों मं जो 70 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है, उसको भाजपा के साथ लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और उनसे संपर्क बढ़ाने के लिए स्नेह यात्राओं का आयोजन किया जाए। य वह मोदी हैं जो कभी मुसलमानों के बारे में मुंह नहीं खोलते थे और वे मुसलमानों को लिबास और हुलिए से अपना निशाना बनाते थे। अब अचानक मोदी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? भारतीय राजनीति पर नजर रखने वाले यह जानते हैं कि 2014 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जे से पूर्व संघ परिवार यह नारा लगाता था, 'जो हिंदू हितों की बात करेगा, वह भारत पर राज करेगा'। अब यह नारा वास्तविक रूप धारण कर चुका है। जितनी भी गैरभाजपा पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रस हो, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर आम आदमी पार्टी, सभी हिंदू हितों की बात कर रहे हैं। मुसलमानों की बात करते हुए उन्हें डर लगता है। आज उनमें से कोई भी पार्टी मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। वजह यह है कि वोट सबको प्यारे हैं और उन्हें 80 प्रतिशत हिंदुओं के वोट चाहिए।

जहां तक मुसलमानों का संबंध है, हाल की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 20-21 करोड़ है, जिनमें से पसमांदा मुसलमानों की आबादी 16-17 करोड़ है, जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। अभी तक देश की इतनी बड़ी आबादी क वोट बैंक की गैरभाजपा पार्टियां बंदरबाट करती आ रही हैं। अब इसमें भाजपा भी अपना हिस्सा चाहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उसमें गरीब मुसलमानों के आठ प्रतिशत वोट भाजपा को मिले हैं। अब भाजपा अपना प्रेमजाल देश भर के पसमांदा मुसलमानों पर फेंकना चाहती है, ताकि उनके वोटों को बटोरा जा सके।

पृष्ठभूमि : देश का मुस्लिम समाज मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित है, जिन्हें अशराफ, अजलाफ और अरजाल कहा जाता है। अशराफ शरीफ (उच्च वर्ग) का बहुवचन है और इसमें मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग सैयद, शेख, पठान, मुगल शामिल हैं। अभी तक मुस्लिम समाज पर इसी वर्ग का वर्चस्व रहा है। जहां तक अजलाफ

का संबंध है, यह जलाफ का बहुवचन है, जिसका अरबी में अर्थ होता है असभ्य। इस वर्ग में आम तौर पर पिछड़ा वर्ग और कारीगर शामिल हैं। जहां तक अरजाल का संबंध है, इसमें आम तौर पर मुस्लिम समाज का सबसे निचला वर्ग शामिल है, जो कि अछूत वर्ग से इस्लाम में शामिल हुआ था। लाख दावा किया जाए कि इस्लाम में जात-पात नहीं है, मगर कड़वी सच्चाई यह है कि इस्लाम भी भारतीय समाज के अन्य वर्गों की तरह विभिन्न जातियों में विभाजित है।

पसमांदा मुसलमानों की मांगों को सबसे पहले पूर्व सांसद अली अनवर ने उठाया था जो ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अली अनवर की बहुचर्चित पुस्तक 'मसावात की जंग' का विमोचन किया था। अनवर का कहना है कि मुसलमानों के बीच जो दलित हैं उनकी स्थिति में तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक उन्हें अनुसूचित जातियों का दर्जा नहीं दिया जाता। इसके लिए भारतीय संविधान की धारा 341 में संशोधन किया जाए, क्योंकि इस धारा के तहत सिर्फ हिंदू अनुसूचित जाति वालों को ही आरक्षण दिया जाता है।

हालांकि अजीब बात यह है कि जो हिंदू, सिख या बौद्ध बन जाते हैं, उनकी आरक्षण की सुविधा बरकरार रहती है, परंतु वे अगर ईसाई या मुसलमान बनते हैं तो उनकी यह सुविधा समाप्त हो जाती है। भारत सरकार द्वारा गठित अनेक आयोगों ने अपनी रिपोर्टों में मुस्लिम समाज में जाति के आधार पर भेदभाव को स्वीकार किया है। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी, जिसमें पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसे वी.पी. सिंह के शासनकाल में लागू किया गया। इसके बाद 79 मुस्लिम जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया। अनवर का कहना है कि मुस्लिम समाज को मिलने वाली सभी सुविधाओं को पांच प्रतिशत अशराफ हड़प जाते हैं। राजनीति, सरकारी नौकरियों, व्यापार, उद्योगों और मीडिया में उच्च जाति के मुसलमानों का वर्चस्व है। 2014 में महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों की 50 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित करके उनके लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई और अदालत ने शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को छोड़कर अन्य सभी आरक्षण को रद्द कर दिया। अनवर का कहना है कि सैयद, शेख, सिद्दीकी, मुगल और पठान जैसी उच्च जातियां अंसारी, धुनिया, नदाफ, हलालखोर, सिकलोगर, सलमानी आदि पिछड़ी जातियों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करते। इस स्थिति को बदलने के लिए यह जरूरी है कि पसमांदा मुसलमानों के लिए भी हिंदुओं की पिछड़ी जातियों की तरह ही आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ■

जनसंख्या नियंत्रण पर मचा विवाद

रोजनामा सहारा (12 जुलाई) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि नवंबर 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे बड़ा देश हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सांख्यिकीय विभाग द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच सकती है। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे हैं, जो विश्व की जनसंख्या का 26 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय दुनिया की कुल जनसंख्या 7 अरब 56 करोड़ है।

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि एक

विशेष संप्रदाय की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने क लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो विभिन्न संप्रदायों के बीच जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा न हो कि एक विशेष संप्रदाय की जनसंख्या तो तेजी से बढ़ जाए और यहां के जो वास्तविक निवासी हैं उनकी आबादी कम हो जाए और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक बन जाएं।

इत्तेमाद (13 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा बढ़ती जनसंख्या की आड़ लेकर देश के बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है। मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि योगी सरासर झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि गत दो दशक में मुसलमानों में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम रही है। इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हाल की रिपोर्ट से भी होती है। बिना कानून के देश की जनता में जो जागृति आई है उसके कारण जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें कहा था कि देश में दो बच्चों से अधिक पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को रोकने के लिए अगर भाजपा कोई कानून लाती है तो वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में छह राज्य ऐसे हैं, जिनमें जनसंख्या की दर कम नहीं हुई है। इनमें मणिपुर, मेघालय और झारखंड भी शामिल हैं। क्या इन राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं? उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर भाजपा बदनाम कर रही है, ताकि उनके खिलाफ देश में माहौल बनाया जा सके। उन्होंने योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुसंख्यक समाज के लिए मूल निवासी शब्द इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति की और कहा कि

क्या मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं हैं? क्या वे विदेशी हैं? उन्होंने कहा कि राष्ट्र की समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।

इत्तेमाद (13 जुलाई) ने अपने संपादकीय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान की निंदा की है, जिनमें उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का सुझाव दिया था। योगी के बयान की निंदा करते हुए समाचारपत्र ने कहा कि भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ देश में माहाल बना रहे हैं, ताकि ध्रुवीकरण करके जनता के वोट बटोरे जा सकें। समाचारपत्र ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए एक जनसंख्या नीति बनाई थी, जिसका प्रारूप पेश किया गया था। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरियां न दी जाए। इसके अतिरिक्त राज्य के विधि आयोग ने भी इस सिफारिश की हिमायत की थी, जिसका जवाब देते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें विधान सभा और संसद के चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि चीन के उदाहरण से यह साफ हो गया है कि कानून बनाकर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

अवधनामा (13 जुलाई) के अनुसार भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को किसी धर्म या जाति से जोड़ना

उचित नहीं है। बल्कि यह पूरे देश के लिए चुनौती है, जिसका हल हमें मिलजुलकर तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट मजहब का नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। मजहब को दीवार बनाकर इस मुसीबत को बढ़ाना न देश के हित में है और न ही समाज के हित में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के लिए समस्या है, मगर उसके लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को निशाना बनाना देश के लिए खतरनाक होगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने 13 जुलाई के संपादकीय में सुझाव दिया है कि देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक स्तर पर जनता में जागृति पैदा करना बहुत जरूरी है। इस बात की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी बजट में वृद्धि की जाए और परिवार नियंत्रण के कार्यक्रम के प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। समाचारपत्र ने कहा है कि कानून बनाकर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता।

रोजनामा सहारा (14 जुलाई) ने कहा है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सांप्रदायिक ताकतें जानबूझकर मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है, ताकि उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। जबकि जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक और सामाजिक समस्या है। इसका धर्म या मजहब से कोई संबंध नहीं है।

रोजनामा सहारा ने 13 जुलाई के संपादकीय में इस बात की निंदा की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसंख्या वृद्धि के लिए जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मुसलमानों में जन्म दर में गत कुछ दशकों में भारी गिरावट आई है। हैरानी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाकर राज्य विधान सभा का चुनाव जीता था, मगर वे अभी तक अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। उनका यह रूख राज्य और देश की एकता के लिए खतरनाक है। भाजपा के नेताओं को चाहिए कि वे उन पर लगाम लगाएं।

पाठ्यपुस्तकों में संशोधन से उभरा नया विवाद

इंकलाब (13 जुलाई) ने अपने मुख्य पृष्ठ के समाचार में इस बात की निंदा की है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) न एक बार फिर विवादित कदम उठाते हुए पाठ्यपुस्तकों में मुसलमानों और मुगलों से संबंधित उद्धरण को हटा दिया है। यहां तक कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी कुछ उद्धरणों को पाठ्यपुस्तकों से निकाल दिया गया है। अनेक शिक्षा विशेषज्ञों ने यह आरोप लगाया है कि एनसीईआरटी ने यह कदम सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव के कारण उठाया है। जबकि एनसीईआरटी का कहना है कि पाठ्यपुस्तकों में संशोधन का सिलसिला निरंतर चलता रहता है और इन उद्धरणों को विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर हटाया गया है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में उनकी कोई जरूरत नहीं थी।

अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के अनुसार एक पुस्तक से पैगम्बर-ए-रसूल से संबंधित अनेक पैराग्राफ हटाए गए हैं। इनमें एक पैराग्राफ यह भी था कि ईसाईयत की तरह इस्लाम एक ऐसा धर्म है, जिसने सबकी समानता और एकता पर जोर दिया है। इसी तरह से सातवीं कक्षा की एक पुस्तक से मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित परिचयात्मक उद्धरणों को हटा लिया गया है। सामाजिक विज्ञान की छठी कक्षा की पुस्तक से एक पैराग्राफ को हटाया गया है, जिसमें कहा गया था कि चंद मुसलमानों के बारे में यह धारणा है

कि वे लड़कियों को शिक्षा देने में रुचि नहीं रखते इसलिए वे उन्हें स्कूल नहीं भेजते। परंतु सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि मुसलमानों में गरीबी एक कारण है, जिसके कारण लड़कियां स्कूल नहीं जातीं या वे शिक्षा अधूरी छोड़ देती हैं।

छठी कक्षा की इतिहास की पुस्तक में सम्राट अशोक से संबंधित अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक संदर्भ को निकाल दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि अशोक के शिलालेख आम लोगों की भाषा में थे और उससे आज भी हमलोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन पुस्तकों में कई सामाजिक आंदोलनों जैसे चिपको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन, नमदा बचाओ आंदोलन और सूचना के अधिकार के कानून से संबंधित आंदोलन को भी इन पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल से संबंधित उद्धरणों को भी तोड़-मोड़कर पेश किया गया है और यह दावा किया गया है कि इस आपातकाल में मानवाधिकारों का व्यापक रूप से हनन हुआ था। लाखों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया था, मीडिया पर सेंसर लगाया गया था और गरीबों को व्यापक पैमाने पर उजाड़ा गया था।

सियासत ने 14 जून के संपादकीय में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। पाठ्यपुस्तकों में बदलाव करके समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है। सरकार जनता को रोजगार उपलब्ध कराने और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बजाय एक बार फिर देश के इतिहास को नई दिशा दे रही है। सरकार एक विशेष विचारधारा को पूरे देश पर जबरन लादने का प्रयास कर रही है। इसलिए उसका विरोध करना हर देशभक्त का कर्तव्य है। आज इस बात की जरूरत है कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जाए। यह हकीकत पूरा दश जानता है कि भाजपा और उसकी विचारधारा से सहमत संगठन देश में मुगल शासकों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि यह वास्तविकता है कि मुसलमानों और खासकर मुगल शासकों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। आज देश के कोने-कोने में मुगलकालीन भवन मौजूद हैं। चाहे वह आगरा का ताजमहल हो या दिल्ली का लाल किला, इन सभी के कारण भारत के शान व शौकत में वृद्धि हो रही है, मगर तंग नजरी और एक विशेष धर्म के खिलाफ भावना के कारण मुगलों को इतिहास से खारिज किया जा रहा है। इससे विश्व भर में सरकार की बदनामी होगी। इसलिए ऐसे प्रयासों से सरकार को बाज आना चाहिए।

सियासत (10 जुलाई) ने अपने संपादकीय में यह शिकायत की है कि कर्नाटक में आरएसएस के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के भाषण को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। इसका विरोध छात्र एवं दलित संगठनों ने किया है और पाठ्यपुस्तक को तैयार करने वाले दस विशेषज्ञों ने त्यागपत्र दे दिए हैं। जबकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि क्योंकि नई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वह छात्रों में विपरीत की जा चुकी हैं इसलिए उनमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है। नई पाठ्यपुस्तकों के समर्थन में भाजपा और संघ के कई संगठनों ने जवाबी अभियान शुरू किया है और उन्होंने कहा है कि अगर पाठ्यपुस्तकों में कोई परिवर्तन किया गया तो वे उसका विरोध करेंगे। कर्नाटक के लिंगायत और बोकालिगा समुदाय ने भी पाठ्यपुस्तकों में संशोधन का विरोध किया है। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में अभी एक वर्ष ही बाकी है इसलिए आने वाले चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भाजपा सरकार पाठ्यपुस्तकों से खिलवाड़ कर रही है और उसे भगवा रंगत दे रही है।

अवधनामा ने 28 जून के संपादकीय में पाठ्यपुस्तकों में किए जा रहे संशोधन का विरोध किया है और कहा है कि आज जो लोग भूमिपुत्र और पुण्यभूमि पर जोर दे रहे हैं वे उसमें मुसलमानों और ईसाईयों को शामिल नहीं करते हैं। जरूरत इस बात की है कि पाठ्यक्रम में इतिहास को निष्पक्ष रूप से पेश किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में सही जानकारो प्राप्त करें। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शत्रुता पैदा करने के लिए जानबूझकर देश के इतिहास को विकृत किया है। हैरानी की बात यह है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा स्कूलों के पाठ्यपुस्तकों में भारी परिवर्तन कर रही है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इन पाठ्यपुस्तकों द्वारा एक विशेष विचारधारा का ही प्रचार हो और उनके बारे में ही जानकारी प्राप्त हो। पुस्तकों से अलबेरूनी और उनकी पुस्तक अल हिंद के उद्धरणों को हटा दिया गया है। इसी तरह से अवध, बंगाल और हैदराबाद में मुस्लिम रियासतों की भूमिका को भी पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है। जबकि राजपूतों, मराठों, सिखों और जाटों की रियासतों से संबंधित सामग्री को यथावत रखा गया है। इनसीईआरटी के निदेशक का दावा है कि किसी राजनीतिक कारण से इन पाठ्यपुस्तकों में संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि इस समय पाठ्यपुस्तकों के संशोधन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अधिकांश सदस्यों का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है।

इत्तेमाद (16 जून) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि भगवा सरकार के दबाव के कारण स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भारी परिवर्तन किया गया है और इसका एक मात्र लक्ष्य हिंदू सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना है। आरएसएस के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के भाषणों और विचारधारा को पाठ्यपुस्तकों में प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में भाजपा शासित अनेक राज्यों जैसे गुजरात, उत्तराखंड एवं हरियाणा के पाठ्यक्रमों में भगवद् गीता को भी शामिल करने की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक बयान में कहा है कि इस वर्ष से नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत वेदों, गीता, रामायण और उत्तराखंड के इतिहास को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाएगा। चिंता की बात यह है कि पाठ्यपुस्तकों में संशोधन राजनीतिक दबाव के कारण किया जा रहा है।

2014 में मोदी के सत्तारूढ़ होन के बाद से ही आरएसएस से संबंधित संगठनों न सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भाजपा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने अपनी रिपोर्ट में पाठ्यपुस्तकों में संशोधन का सुझाव दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि स्कूल की पुस्तकों में बहुत सी ऐतिहासिक हस्तियों को गलत ढंग से पेश किया गया है, इसलिए उसमें संशोधन करना जरूरी है। इस संसदीय कमेटी ने हिंदू धर्म ग्रंथों को भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने की सलाह दी थी।

सीबीएसई की पुस्तकों से भी कई उद्धरणों को खारिज करने का सुझाव दिया गया है जो कि इस्लामिक राज्यों के उत्थान, मुगल दरबारों के इतिहास, वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलनों से संबंधित हैं। हैरानी की बात यह है कि कई पाठ्यपुस्तकों में से फैज अहमद फैज की कविताओं को भी हटा दिया गया है। जब से भाजपा सत्ता में आई है इसका बड़ा और महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि उनकी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति में संशोधन किया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने की बजाय धार्मिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया जाए। आज की सरकार पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की नीतियों को बदलना चाहती है जो देशहित में नहीं है।

विश्व

शरिया लागू करने के लिए तालिबान कटिबद्ध

इत्तेमाद (3 जुलाई) के अनुसार तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा पहली बार जनता के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान में संपूर्ण इस्लामिक व्यवस्था को लागू करेंगे। हमें निजाम-ए-मुस्तफा लागू करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। बाहर के देश हमें यह न बताएं कि हमें अफगानिस्तान को कैसे चलाना चाहिए? उन्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। दुनिया भर की गर मुस्लिम कौमें हमेशा से इस्लाम और इस्लामिक रियासत का विरोध करती आ रही हैं। हमें उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए और अल्लाह व कुरान के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने अफगानों से अनुरोध किया कि वे आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हों। कौम के विभाजन से देश विखंडित हो जाते हैं और हुकूमतें बिखर जाती हैं। उलेमा को चाहिए कि वे शासकों की गलतियों का मीडिया में प्रचार करने की बजाय उनसे सीधा बातचीत करें और निजाम-ए-मुस्तफा को लागू करने में हुई त्रुटियों के बारे में उनका ध्यान दिलाएं। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह का शुक्र है कि अफगानिस्तान आजाद है। हम इंसानों के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों का हर कीमत पर पालन करेंगे। अफगान अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं है। उन्होंने पूंजीपतियों और व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे आगे आएं और अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमने विदेशी सहायता पर निर्भर रहने का प्रयास किया तो अमेरिका और यूरोप हमें आर्थिक रूप से गुलाम बना लेंगे। हम जनता के शासक नहीं बल्कि उनक गुलाम हैं। अल्लाह ने कुरान पाक और शरीयत में हमें जो निर्देश दिए हैं, हम उन सभी का सख्ती से पालन करेंगे।

हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने पश्तो भाषा में कौम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तालिबान को यह अधिकार है कि वह निजाम-ए-मुस्तफा को लागू करे। हमारा यह फैसला अफगान जनता के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक शुभ संदेश है। मुल्ला हिबतुल्लाह ने कहा कि हम कभी भी अफगान जनता को अपना निशाना बनाने के पक्ष में नहीं रहे हैं, मगर जो अफगान नागरिक विदेशियों के हाथ में कठपुतली बने हुए थे, उनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जब अमेरिकी अफगानिस्तान से निकले तो हमने आम माफी की घोषणा कर दी और हमने उन्हें कहा कि हालांकि उन्होंने हम पर जुल्म ढाए हैं, मगर अल्लाह के नाम पर हम उन्हें माफ करते हैं। मुल्ला हिबतुल्लाह ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि वे भ्रष्टाचार का हर कीमत पर खात्मा करें और निष्पक्ष रूप से जनता को प्रशासन देने का प्रयास करें। अगर ये बुराईयां हमारे प्रशासन में रहीं तो यह हमारे उस संघर्ष के विपरीत होगा, जो

हमने इस देश में इस्लामिक प्रशासन को लाने के लिए किया था। उन्होंने कहा कि विश्व की बड़ी-बड़ी ताकतें इस्लाम के खिलाफ हैं। वे यह नहीं चाहती हैं कि अफगानिस्तान में निजाम-ए-मुस्तफा को लागू किया जाए। जब हम शरीयत को लागू करेंगे तो ये ताकतें हमारा विरोध करेंगी, मगर हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। हम विदशी और आंतरिक चुनौतियों का पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार हैं। हम शरा और रसूल के खिलाफ किसी को भी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने इस्लामिक उलेमा से कहा है कि वे सरकार का मार्गदर्शन करें कि इस्लामिक शरीयत को कैसे लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक न तो किसी इस्लामिक और न ही गैर इस्लामिक देश ने हमें मान्यता दी है।

सियासत (27 जून) ने अपने संपादकीय में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि

अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के उच्चाधिकारियों की एक टीम ने अफगानिस्तान का दौरा किया था और भारत काबुल में अपना दूतावास पुनः खोलने पर विचार कर रहा है। भूकंप से तबाह हुए अफगानिस्तान को भारत की मोदी सरकार ने जो सहायता दी है उसके कारण वहां पर भारत के प्रति सद्भावना में वृद्धि हुई है।

डेनमार्क में जिहादी हमला

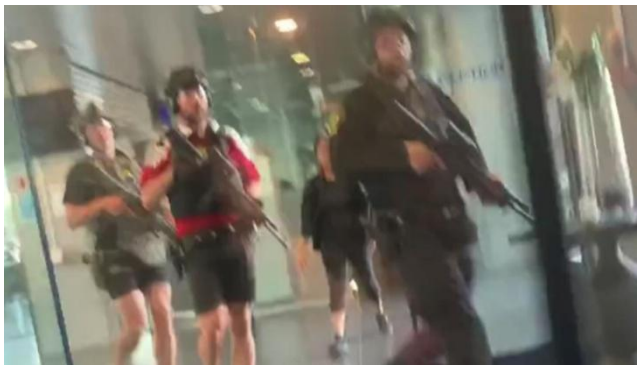

इत्तेमाद (5 जुलाई) के अनुसार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहैगन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिनमें तीन व्यक्ति मारे गए और अनेक घायल हो गए। कोपेनहैगन के पुलिस प्रमुख सोरेन थॉमसन ने बताया कि आक्रमणकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक रायफल और कुछ गोलियां भी बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का संदेह है कि इस वारदात में इस्लामिक अतिवादी गुटों का हाथ है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमलावर के अन्य सहयोगियों का सुराग लगा रही है और इस बात का भी पता लगा रहो है कि उसका संबंध किस अतिवादी आतंकी संगठन से है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि हम इस हमले के पीछे की साजिश का पता लगा रहे हैं। यह घटना उस समय घटित हुई जब मासूम

बच्चे और उनके परिवारजन शॉपिंग में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा देश इस्लामिक आतंकवाद से प्रभावित नहीं था, मगर अब वह स्थिति नहीं रही है। पुलिस ने इस व्यक्ति के साथियों की तलाश के लिए राष्ट्रव्यापी खोजी अभियान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि पिछले सप्ताह ही नार्वे की राजधानी ओस्लो में एक इस्लामिक आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें दो लोग मारे गए थे और 21 घायल हो गए थे। यह पहला अवसर है जब इन दोनों देशों में आतंकियों ने हिंसा की ज्वाला भड़काई है।

रूसी खतरे का सामना करने के लिए नाटो की नई कमान

हमारा समाज (1 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो देशों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है कि यूरोप में नाटो देशों के सैनिकों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, ताकि रूस के बढ़ते हुए खतरे का सामना किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के आक्रामक इरादों को देखते हुए यह जरूरी है कि नाटो देशों की एकता पर जोर दिया जाए और उन्हें सैनिक दृष्टि से सशक्त बनाया जाए। इसी कार्यक्रम के तहत यूरोप में अमेरिकी नौसेना की शक्ति में भी वृद्धि की जा रही है। स्पेन में नौसेना के चार जलयानो के समूह को बढ़ाकर छह किया जा रहा है। पोलैंड में सेना का एक मुख्यालय स्थापित किया गया है और रोमानिया में एक नया ब्रिगेड तैनात किया जा रहा है। 5 हजार नए सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका एफ-35 युद्ध विमानों के दो अतिरिक्त दस्ते को ब्रिटेन में तैनात कर रहा है। जर्मनी और इटली की भी रक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। हम रूस को हर कीमत पर रोकने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नाटो में दो नए देश फिनलैंड और स्वीडन को भी शामिल किया जा रहा है।

कौमी तंजीम (2 जुलाई) ने नाटो देशों के सैनिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए कहा है कि हाल ही में मास्को और बीजिंग के बीच जो गठजोड़ हुआ है, उससे पूर्वी यूरोप के लिए खतरा

बढ़ गया है। यही कारण है कि नाटो संधि में शामिल देशों द्वारा पोलैंड और रोमानिया को सैनिक दृष्टि से सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि रूस के विस्तारवादी इरादों पर लगाम लगाई जा सके। बाल्कन की रियासतें अब भी खतरों से घिरी हुई हैं। वहां पर लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। रोमानिया और पोलैंड यूक्रेन में रूस के बढ़ते हुए विस्तारवाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि तुर्की मध्य-पूर्व और बाल्कन प्रायद्वीप में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बुल्गारिया अभी तक दुविधा में है। इसी तरह से स्लोवाकिया और चेक गणराज्य में भी शासक दुविधा के शिकार हैं। वहां का राष्ट्रपति अगर रूस का समर्थन करता है तो प्रधानमंत्री नाटो को प्रमुखता देता है। बुल्गारिया उत्तरी मैसेडोनिया को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और वह अब भी ग्रेटर अल्बानिया बनाने का स्वप्न देख रहा है। सर्बिया ने हाल ही में रूस का हाथ थामा है। पूर्वी यूरोप के देशों के आंतरिक मतभेदों के कारण रूस की स्थिति सुधर रही है। रूस इस बात का प्रयास कर रहा है कि इन देशों में नाटो और अमेरिका क प्रभाव का समाप्त किया जाए। ऐसे में यह जरूरी है कि अमेरिका और नाटो पूर्वी यूरोप के देशों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करे।

सियासत (1 जुलाई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर संतोष प्रकट किया है कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना लगभग तय हो गया है। अभी तक तुर्की इन देशों को नाटो में शामिल करने का विरोध कर रहा था, मगर अमेरिका के दबाव के कारण अब तुर्की ने अपने रूख में नरमी लाई है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात पर जोर दिया है कि तुर्की विरोधी कुर्द जो स्वीडन में डेरा डाले हुए हैं, उन्हें तुर्की के हवाले किया जाए। स्वीडन और फिनलैंड ने इस बात की घोषणा की है कि वे अपने देशों में तुर्की के खिलाफ किसी कारवाई को प्रोत्साहन नहीं देंगे, मगर इससे तुर्की संतुष्ट नहीं है और उसने पुनः यह मांग की है कि फिनलैंड में 12 और स्वीडन में जो 21 तुर्की विरोधी नेता हैं, उन्हें तुर्की के हवाले किया जाए। तुर्की ने यह मांग की है कि अमेरिका प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाए। इन विद्रोहियों ने 2016 में एर्दोगान की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी, जो विफल हो गई थी। तुर्की के दबाव पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कुर्दिस्ताव वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अब स्वीडन और फिनलंड ने भी यह घोषणा की है कि वे तुर्की क किसी विद्रोही को कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे। अभी तक स्वीडन और फिनलैंड को तटस्थ देश माना जाता था, मगर यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद इन दोनों देशों ने नाटो और अमेरिका का हाथ थामा है।

शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयास

इंकलाब (9 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारा जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से काफी लंबी बातचोत की और इस बात पर जोर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में जो तनाव आया था उसे दूर किया जाए। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की मांग की। अमेरिका ने भी अपने व्यापारिक सलाहकार दिलावर सईद को पाकिस्तान भेजा है और वे वहां के व्यापारियों से बातचीत करने में लगे हुए हैं।

पाकिस्तान अमेरिका को हर वर्ष लगभग छह अरब डॉलर का माल भेजता है। अब पाकिस्तान सरकार इसमें और भी वृद्धि करना चाहती है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान को इस बात का भी भय है कि अफगानिस्तान में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उनके कारण पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या खतरनाक रूप धारण कर सकती है। इसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से सहयोग की आशा कर रहा है।

गौरतलब है कि अप्रैल महीने में पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में विरोधी पक्ष की ओर से पेश अविश्वास प्रस्ताव के कारण इमरान सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार का तख्ता पलटने के पीछे अमेरिका का हाथ है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस आरोप का खंडन किया गया था, मगर इस आरोप के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए यह जरूरी है कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों में सुधार हो। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है, जबकि भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में काफी सुधार हुआ है।

अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग से दर्जनों की हत्या

इंकलाब (6 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राज्य इलिनॉयस में स्वतंत्रता दिवस परेड में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाने के कारण छह व्यक्ति मौके पर मारे गए और 24 घायल हो गए। हाईलैंड पार्क पुलिस ने दावा किया है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध व्यक्ति की उम्र 22 वर्ष है और उसका नाम रॉबर्ट ई. करीमो बताया जाता है। पुलिस इस

संबंध में जांच कर रही है कि उसका संबंध किस आतंकवादी संगठन से है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस परेड के मौके पर अमेरिका में कुछ अन्य स्थानों पर भी अतिवादियों ने गोली चलाई, जिसके कारण कम-से-कम 12 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। इनमें से 9 व्यक्तियों की हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है।

मीडिया के अनुसार अमेरिका में हिंसक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि अस्त्र-शस्त्रों की खरीद को कैसे नियंत्रित किया जा सके। गौरतलब है कि दो महीने पूर्व न्यूयॉर्क में 10 अश्वेत दुकानदारों को कुछ आक्रमणकारियों ने गोली से उड़ा दिया था और टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल में एक किशोर ने 12 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन घटनाओं पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह की हिंसक घटनाओं की जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि मैं गन कल्चर को समाप्त करके ही दम लूंगा। मेरे लिए यह जरूरी है कि अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

इंकलाब (4 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क ने एक कानून पास करके टाइम्स स्क्वायर आदि अनेक सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि दो सप्ताह पूर्व अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी संविधान के मूल भावना के विपरीत बताते हुए हथियारों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य की विधान सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया था, जिसमें हथियारों से होने वाली मौतां को रोकने के लिए कानून बनाने पर जोर दिया गया था। गवर्नर ने यह दावा किया था कि अमेरिका के 50 राज्यों में से न्यूयॉर्क एक ऐसा राज्य है जहां पर गोली चलने के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा था कि इस बात की जरूरत है कि हथियारां की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि लोग मासूम नागरिकों के जान से न खेल सकें।

एक अन्य समाचार के अनुसार अमेरिका के केंटकी राज्य में एक अपराधी ने तीन पुलिसकर्मियों को गोली मारकर हत्या कर दी। बीबीसी के अनुसार 49 वर्षीय हत्यारे को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जाता है कि इस व्यक्ति का अपने परिवारजनों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो उसने गोली चलाकर तीन पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी।

पश्चिम एशिया

हिजबुल्लाह के खिलाफ 30 देशों का मोर्चा

मुंबई उर्दू न्यूज (3 जुलाई) के अनुसार तीस से अधिक देशों ने लेबनान क इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार यह सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ था और इसमें तीस से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के कारण विश्व के सामने आने वाले खतरे पर विचार किया गया और उसे रोकने के लिए एकजुट होकर कार्रवाई करने का फैसला किया गया। बताया जाता है कि एलईसीजी नामक इस संगठन का यह नौवां अधिवेशन था। प्रवक्ता ने उस स्थान का नाम बताने से इंकार कर दिया, जिसमें इस संगठन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में हिजबुल्लाह के आतंकवादी मंसूबों, उसके द्वारा अस्त्र-शस्त्रों की खरीदारी और उसक आर्थिक ढांचे के संबंध में विस्तृत रूप से विचार किया गया। इस अधिवेशन में इस बात पर भी विचार किया गया कि हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों के खात्मे के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस संगठन के अधिवेशन में मध्य-पूर्व, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, अफ्रीका, इंडो-पैसिफिक देश, उत्तरी अमेरिका और यूरोपोल के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें से अधिकांश देश पहले ही हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं।

दूसरी ओर हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका मुख्य लक्ष्य इजरायल के विस्तार को रोकना है। इजरायल के साथ उसका कई बार युद्ध भी हो चुका है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर रखा है।

क्या है हिजबुल्लाह?

हिजबुल्लाह शिया मुसलमानों का एक आतंकी संगठन है, जिसका मुख्यालय लेबनान में

स्थित है। इसका मुख्य लक्ष्य मध्य-पूर्व में इजरायल और पश्चिम के ईसाई देशों के प्रभाव को रोकना है। इस संगठन के कई अंग हैं। जहां तक इस संगठन की पृष्ठभूमि का संबंध है, 1943 में लेबनान फ्रांसीसी गुलामी से आजाद हुआ था और वहां पर यह व्यवस्था बनाई गई थी कि ईसाई और मुसलमान बारी-बारी सत्ता में भागीदार होंगे। 1971 में फिलिस्तीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मुख्यालय जॉर्डन से लेबनान में स्थानांतरण कर लिया। 1983 में बैरूत में हिजबुल्लाह ने अमेरिकी दूतावास पर हमला करके 63 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने आत्मघाती हमलों में अमेरिका और फ्रांस के 305 सैनिकों की हत्या कर दी। एक अमेरिकी न्यायालय ने इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ बताया। 1984 में हिजबुल्लाह ने एक कार बम द्वारा बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास के दर्जनों लोगों की हत्या कर दो। 1985 में हिजबुल्लाह ने अपना पहला घोषणापत्र जारी किया। 1992 में अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास पर हमला करके हिजबुल्लाह ने अनेक लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद इस संगठन का महासचिव हसन नसरल्लाह बना। हिजबुल्लाह ने चुनाव में भी भाग लिया और संसद की आठ सीटों पर विजय प्राप्त की। 1989 में सऊदी अरब के हस्तक्षेप से गृहयुद्ध समाप्त हुआ और सीरिया की देख-रेख में इसे लेबनान को दे दिया गया। इस समझौते में यह भी तय हुआ कि सभी सशस्त्र संगठनों को निरस्त्र करना होगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे मानने से इंकार कर दिया। 1994 में इस संगठन ने लंदन और अर्जेंटोना में इजरायली दूतावासों पर हमले किए। 1997 में अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 2005 में हिजबुल्लाह ने लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरिरी की हत्या कर दी। 2006 में हिजबुल्लाह ने दो इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसका इजरायल के साथ युद्ध छिड़ गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2011 में जब सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह ने वहां के राष्ट्रपति बशर अल-असद की सहायता के लिए अपने सैकड़ों लड़ाकुओं को सीरिया भेजा। 2012 में बुल्गारिया में हिजबुल्लाह ने छह इजरायली पर्यटकों की हत्या कर दी। 2013 में यूरोपीय यूनियन ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 2019 में हिजबुल्लाह के दबाव के कारण लेबनान के तत्कालीन प्रधानमंत्री साद हरिरी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 2020 में जब ईरान के एक कमांडर कासिम सुलेमानी की इराक में हत्या कर दी गई तो उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन से हमले किए।

इस समय हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरल्लाह है, क्योंकि इससे पूर्व इजरायली गुप्तचर संगठन ने तत्कालीन हिजबुल्लाह प्रमुख अब्बास अल-मुसावी की हत्या कर दी थी। जहां तक हिजबुल्लाह के नेतृत्व का संबंध है, इसका संचालन सात सदस्यीय शूरा काउंसिल करती है, जिसके तहत पांच उपपरिषद हैं, जिनमें राजनीतिक असेंबली, जिहाद असेंबली, संसदीय असेंबली, कार्यकारिणी असेंबली और न्यायिक असेंबली शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार हिजबुल्लाह के पास हजारों सशस्त्र लड़ाकू हैं और इसके समर्थक विश्व भर में फैल हुए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह धीरे-धीरे अपने मकड़जाल को विश्व भर में फैला रहा है और कई अन्य देशों में हाल ही में इसने अपने कार्यालय भी स्थापित किए हैं।

सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेद उभरे

सऊदी अरब में हज संपन्न हो गया है और इसमें विश्व भर के दस लाख मुसलमानों ने भाग लिया है। अब हाजियों ने अपने देश लौटना शुरू कर दिया है। इस हज के दौरान एक बार फिर ईरान और सऊदी अरब के मतभेद उभरकर सामने आए हैं। इससे इस्लामिक एकता को गहरा झटका लगा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 जुलाई) के अनुसार मैदान-ए-अराफात में ईरानी हाजियों ने एक अलग सभा का आयोजन किया, जिसमें फिलिस्तीन की आजादी के लिए संघर्ष शुरू करने की घोषणा की गई। ईरान के धार्मिक प्रमुख सैयद अली खामेनेई ने अपना विशेष पैगाम-ए-हज जारी करके मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। इसके बावजूद ईरानी हाजियों ने अराफात में अपने सम्मेलन में साम्राज्यवादी ताकतों और इजरायली सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और फिलिस्तीनियों के समर्थन का ऐलान किया। इस अवसर पर एक पांच सूत्री कार्यक्रम की भी घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि यरुशलम को यहूदी कब्जे से मुक्त कराना प्रत्येक मुसलमान की जिम्मेवारी है और इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम देश इजरायल के साथ किसी तरह का संबंध न रखे, क्योंकि इससे मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न होते हैं।

रोचक बात यह है कि इस सम्मेलन में शिया धार्मिक आस्था के अनुसार दुआ-ए-अराफा भी पढ़ी गई। इस सम्मेलन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के दबाव पर सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रस्ताव द्वारा सऊदी अरब की सुन्नी सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। हाल ही में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों में इजरायल की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। पांच मुस्लिम अरब देश इजरायल को मान्यता भी दे चुके हैं, इनमें मिस्र, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन शामिल हैं। इनके अतिरिक्त इस्लामिक देश सूडान ने भी हाल ही में इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। ईरान द्वारा इसका खुलेआम विरोध किया गया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अराफात के मैदान

में ईरानियों द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन करने से ईरान और सऊदी अरब के संबंधों को एक और झटका लगा है। यह पहला अवसर है जब ईरान ने खुलेआम सऊदी अरब के शासक परिवार की आलोचना की है।

दूसरी ओर **मुंबई उर्दू न्यूज** (8 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल-मुजीब ने कहा है कि जो लोग हज पर आए हैं वे अल्लाह के मेहमान हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना हर मुसलमान का कर्तव्य है, मगर हज के लिए आने वाले व्यक्ति को किसी भी सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हज के दौरान जिस किसी ने राजनीति करने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाजियों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए 20 विशेष कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जुलाई) के अनुसार साढ़े तीन लाख हाजियों ने मदीना में मोहम्मद साहब के मजार पर हाजिरी दी।

हमारा समाज (5 जुलाई) के अनुसार पुरानी घोषणा के विपरीत सऊदी अरब सरकार ने यह तय किया है कि हज करने के लिए आने वाले प्रत्येक हाजी को अपने साथ स्वदेश ले जाने के लिए आब-ए-जमजम भी तोहफे के तौर पर पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व सऊदी सरकार ने आब-ए-जमजम को देश से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सियासत (1 जुलाई) के अनुसार सऊदी अरब ने हज शुरू होने से पूर्व इस बात की घोषणा की थी कि जो हाजी बिना कोटे के हज यात्रा करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाचारपत्र के अनुसार सऊदी सरकार ने 500 से अधिक ऐसे व्यक्तियों पर दस-दस हजार रियाल जुर्माना किया है जो बिना अनुमति के हज यात्रा करने क लिए आए थे। सऊदी पुलिस ने हाजियों से धोखा करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो सऊदी नागरिक और अन्य विदेशी लोग हैं।

हमारा समाज (6 जुलाई) के अनुसार हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए सऊदी सेना को विशेष रूप से निर्देश दिए गए थे। समाचारपत्र ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सुरक्षाकर्मियों ने हज यात्रियों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

सियासत (7 जुलाई) के अनुसार हज यात्रा के दौरान सरकार की ओर से सात विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था, जिनमें इस्लामिक धर्म, संस्कृति और सऊदी अरब में हो रहे विकास को दिखाया गया था।

ईद के अवसर पर 1500 कैदी रिहा

रोजनामा सहारा (11 जुलाई) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के अमीर शेख मोहम्मद बिन जायेद अल-नाहयान ने अबुधाबी में 727 कैदियों को ईद के अवसर पर जेलों से रिहा करने की घोषणा की है। जो लोग जुर्माना अदा न करने के कारण जेलों में बंद थे, उनकी ओर से जुर्माना का भुगतान सरकारी खजाने से किया गया है। इसी तरह से दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल-मकतूम ने भी ईद के मौके पर दुबई की जेलों से 505 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात की एक और रियासत रास अल खैमाह के शासक शेख सउद बिन सकर अल-कासिमी ने 251 कैदियों की रिहाई का फरमान जारी किया है। ईद के अवसर पर पूरे संयुक्त अरब अमीरात में एक सप्ताह के अवकाश की घोषणा की गई है।

तुर्की में वॉयस ऑफ अमेरिका के प्रसारण पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (3 जुलाई) के अनुसार तुर्की में वॉयस ऑफ अमेरिका के प्रसारण को सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पूर्व जर्मन रेडियो के प्रसारण को भी प्रतिबंधित किया गया था। तुर्की के मीडिया नियामक संगठन ने दावा किया है कि इन दोनों संगठनों ने तुर्की में प्रसारण की अनुमति प्राप्त नहीं की थी। वैश्विक मीडिया ने इस प्रतिबंध की निंदा की है और कहा है कि यह प्रेस की आजादी पर हमला है। तुर्की के निवासियों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे अपनी पसंद के प्रसारण को सुनें।

वॉयस ऑफ अमेरिका की निदेशक योलांडा लोपेज ने कहा है कि यह सेंसरशिप की कोशिश है। तुर्की सरकार ने हमारी वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया है। हालांकि हम तुर्की की जनता को उनकी भाषा में निष्पक्ष समाचार उपलब्ध करवाया करते थे। उन्होंने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है।

ईरान के खिलाफ प्रतिबंध गैरकानूनी

अवधनामा (2 जुलाई) के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वे गैरकानूनी हैं। जब तक इन प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाता ईरान के साथ पश्चिमी देशों की वार्ता सफल नहीं हो सकती। उन्होंन कहा कि ईरान परमाणु शक्ति का विकास शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन भी ईरानी परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद इसकी पुष्टि कर चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को दिए गए किसी भी आश्वासन का उल्लंघन नहीं किया है।

रईसी ने कहा कि यह आरोप राजनीतिक उद्देश्यों से लगाए जा रहे हैं। ईरान अपने खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को गैरकानूनी और जालिमाना समझता है और वह अपनी रक्षा के लिए उठाए गए सभी कदमों का अपना अधिकार समझता है। इन गैरकानूनी प्रतिबंधों को विफल बनाने के लिए ईरान अपने प्रयासों को जारी रखेगा।

इत्तेमाद (7 जुलाई) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हसन अमीर अब्दुल्लाहियां ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि वह ईरान विरोधी अपनी नीति में संशोधन करे। जब तक अमेरिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, दोहा सम्मेलन की सफलता संदिग्ध है। ईरान ने पश्चिमी देशों का जो आश्वासन दिए थे, उन्हें पूरा किया है। अब यह पश्चिमी देशों पर ह कि वे अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तनाव की समाप्ति नहीं हो सकती। तनाव की समाप्ति सभी पक्षों के हित में है।

अन्य

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में भारतीय दूसरे स्थान पर

रोजनामा सहारा (4 जुलाई) के अनुसार इस वर्ष जिन विदेशियों ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की है, उनमें भारत का स्थान दूसरा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिका की नागरिकता लेने वाले सबसे ज्यादा मैक्सिको के नागरिक हैं, जिनकी संख्या 24,508 है। दूसरे स्थान पर भारत है, जिसके 12,928 नागरिकों ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की है। अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा की निदेशक उर एम. जद्दौ ने कहा है कि 2021 में 8 लाख 55 हजार लोगों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई थी। जबकि इस वर्ष के 15 जून तक 6 लाख 61 हजार 500 व्यक्तियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिन लोगों ने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की है उनमें से 34 प्रतिशत लोग मैक्सिको, भारत, फिलीपींस, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के हैं।

मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार

रोजनामा सहारा (4 जुलाई) के अनुसार उदयपुर और अमरावती में जिस तरह से निर्दोष हिंदुओं की हत्या की गई है, उसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए मानेसर में बाबा भीष्मनाथ मंदिर में हिंदू संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में यह फैसला किया गया कि इस क्षेत्र में जो बाहरी लोग रह रहे हैं उनका सुराग लगाकर उनके बारे में प्रशासन को सूचित किया जाएगा, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी मुस्लिम दुकानदार से सामान न खरीदा जाए।

मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करने की मांग

सियासत (8 जुलाई) के अनुसार जम्मू-कश्मीर के इस्लामिक विद्वानों और प्रचारकों की शीर्ष संस्था मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) की ओर से श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बात की मांग की गई है कि अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को तुरंत रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रशासन से यह भी मांग की गई है कि कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद केंद्रीय जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज को नियमित किया जाए और उसमें किसी तरह की रूकावट नहीं डाली जाए। मांग करने वालों में दारूल उलूम रहमानिया (बांदीपुर), जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती आजम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अंजुमन शरई शेखान, जमीयत अहले

हदीस, जमात-ए-इस्लामी, कारवां-ए-इस्लामी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम, अंजुमन तब्लीगी इस्लाम, जमीयत-ए-हमदानिया, अंजुमन नुसरत-उल-इस्लाम, अहले हदीस फाउंडेशन, वक्फ इस्लामिया, मोहम्मद ट्रस्ट आदि 25 मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी

मुंबई उर्दू न्यूज (5 जुलाई) के अनुसार मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी की ओर से मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में जारी किया गया है। किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सुमैया की ओर से दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में राउत को मझगांव की अदालत में पेश होना था, मगर वे पेश नहीं हुए। इस पर यह वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि मई में मेधा सुमैया ने राउत के खिलाफ 100 करोड़ के घोटाले के सिलसिले में मानहानि की एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राउत ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं और यह समाचार मीडिया में प्रकाशित होने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

यह समाचार शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने अदालत से यह मांग को थी कि शिवसेना के मुखपत्र में इस आरोप के खिलाफ माफीनामा प्रकाशित किया जाए।

गाय की कुर्बानी न करने का निर्देश

कौमी तंजीम (9 जुलाई) के अनुसार दारूल उलूम देवबंद ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि वे ईद के मौके पर गोवंश की कुर्बानी न करें, क्योंकि इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। देश के मुसलमानों को कानून का पालन करना चाहिए और इस बात का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, जिससे समाज के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचे।

गौरतलब है कि हर वर्ष ईद के मोके पर दारूल उलूम देवबंद की ओर से देश के मुसलमानों के नाम अपील जारी की जाती है कि वे गोवंश के वध पर लगे हुए प्रतिबंध का सम्मान करें और ईद के अवसर पर गोवंश की कुर्बानी न दें। दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने देश के मुसलमानों को यह भी निर्देश दिया था कि व सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करें और पशुओं के अवशेष सार्वजनिक स्थानों पर न फेकें। न ही कुर्बानी के बारे में कोई वीडियो प्रसारित करें और नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ें।

RNI No. DELHIN/2017/72722

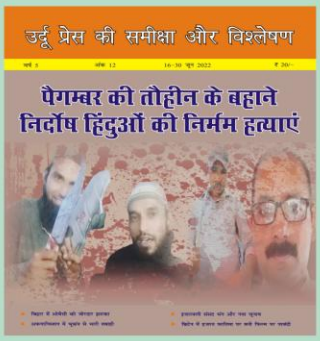

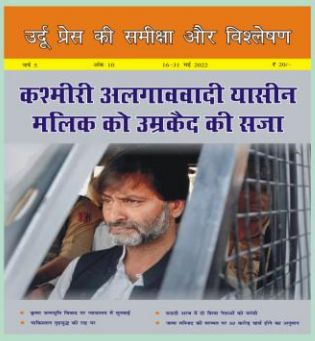

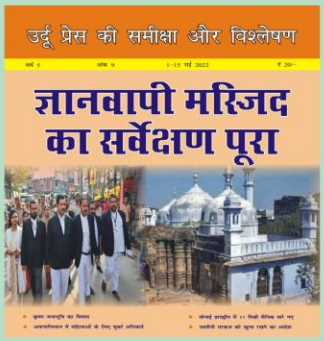

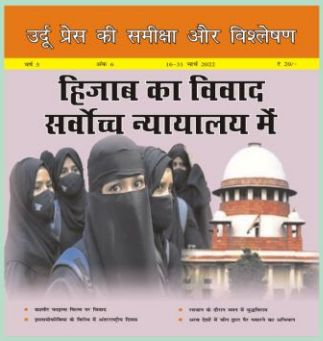

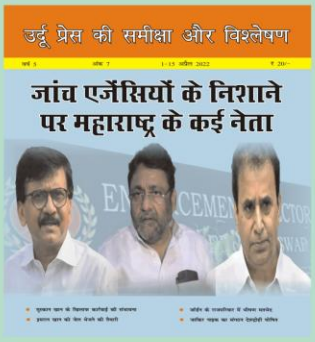

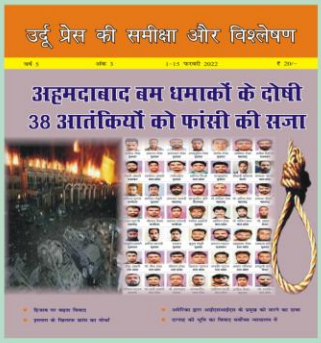

|| प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ||

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in